

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही  
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री पुष्पमित्र सिंह देव पुत्र श्री जी. रामचन्द्र, जाति-मीणा, निवासी- खारची, जिला-पाली  
बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही
2. स्व. श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही के उत्तराधिकारी:-
  - 2/1. श्री लीलाराम पुत्र बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही
  - 2/2. श्री भीमाराम पुत्र बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही
  - 2/3. सुकी पुत्री बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही
  - 2/4. सदी पुत्री बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही
  - 2/5. श्रीमती राउ पत्नि बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील- सिरोही
  - 2/6. किशन पुत्र स्व. श्री फूसाराम पुत्र स्व. बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील व जिला- सिरोही
  - 2/7. गुडिया पुत्री स्व. श्री फूसाराम पुत्र स्व. बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील व जिला- सिरोही
  - 2/8. अतीया पुत्री स्व. श्री फूसाराम पुत्र स्व. बाबलाजी, जाति- भील, निवासी- जैला, तहसील व जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 02/2018

“अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, प्रत्यर्थी संख्या- 2/1 से 2/5 की ओर से
3. परोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 17 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या: 01/2010 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 से व्यथित होकर प्रत्यर्थागण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थागण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या- 2/1, 2/5. व 2/7 की ओर से पूर्व में अधिवक्ता श्री हरजीराम चौधरी उपस्थित हुये।

.....पेज दो पर

तत्पश्चात् प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 2/1 से 2/5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा उपस्थित। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 2/6 से 2/8 को सम्मन की तामिल होने के ब्रौद भी उपस्थित नहीं हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव ग्राम सिरोही के खसरा संख्या-618/1/1, 622/1, 623, 624/1, 707, 761, 763, 764/1, 770/1 कुल किता 9 कुल रकबा 57 बीघा 9 बिस्वा का रेकर्डेड खातेदार कृषक है। इस भूमि के लिये नायब तहसीलदार, सिरोही ने दिनांक 19.6.1996 को धारा 61(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त भूमि को परित्याग करने की घोषणा कर कब्जे सरकार लेने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ। तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति-भील, निवासी- जैला ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए उजरदारी प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात् बाबला भील ने प्रकरण में न्याय नहीं मिल पाने के संबंध में जिला कलक्टर, सिरोही को आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु अनुरोध किया। जिस पर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के न्यायालय में स्थानान्तरण हुआ, उसके बाद तहसीलदार, रेवदर के न्यायालय में स्थानान्तरण हुआ एवं अन्त में प्रकरण सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के न्यायालय को स्थानान्तरित किया गया। सहायक कलक्टर न्यायालय, आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/96, 44/97, 51/99 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2000 के द्वारा विवादित भूमि को कब्जे सरकार लेने का आदेश दिया गया। जिसकी पालना में उक्त कृषि भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज किया गया। सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2000 के विरुद्ध उक्त श्री बाबला भील द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 18.6.2001 को खारिज हुई। तत्पश्चात् उक्त श्री बाबला भील ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के निर्णय दिनांक 18.6.2001 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रकरण संख्या:अपील/डिक्री/134/01/सिरोही (4330/01) पर दर्ज होकर बाद सुनवाई पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2010 के द्वारा सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के निर्णय दिनांक 12.12.2000 व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के निर्णय दिनांक 18.6.2001 को निरस्त करते हुये वर्तमान अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव व उक्त श्री बाबला को सुनवाई व साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को प्रतिप्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 01/2010 दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव ने उजरदारी प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार, सिरोही के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.6.1996 को खारिज करने का

.....पेज तीन पर

अनुरोध किया। इसके अलावा, अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही में धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 14.6.2010 के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कर राजस्व रेकॉर्ड में अपीलार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर कब्जा दिलाने जाने का भी अनुरोध किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन को दिनांक 04.12.2017 को यह दर्शाते हुए खारिज कर दिया कि यह अधिकार मात्र राजस्व मण्डल, अजमेर में ही निहित है। तहसीलदार, सिरौही द्वारा धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन को खारिज करने का पारित निर्णय विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय व विधिक दृष्टान्तों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में उस न्यायालय के आदेश के प्रभाव के कारण राजस्व रेकॉर्ड में परिवर्तन किया गया हो तो उस आदेश के निरस्त होने पर रेकॉर्ड को पूर्व की स्थिति में लाना अनिवार्य व न्यायसंगत है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही ने इस तर्क को गंभीरता से नहीं लेकर त्रुटि पूर्ण आदेश पारित किया है। जबकि अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव विवादित भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार कृषक है एवं अपीलार्थी पर प्रकरण के नोटिस की तामिली के अभाव में सहायक कलक्टर, आवृत्त व राजस्व अपील अधिकारी के निर्णयों को अपास्त करते हुए प्रकरण साक्ष्य लेने व सुनवाई का समुचित अवसर देने के निर्देश के साथ तहसीलदार, सिरौही को प्रतिप्रेषित किये जाने से पूर्व में पारित आदेश व उस आदेश के कारण राजस्व रेकॉर्ड में किये गये परिवर्तन निष्प्रभावी होकर निरस्त हो जाने से अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव का आवेदन अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता कानूनन स्वीकार योग्य होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 विधि विरुद्ध व निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का यह अभिमत गलत है कि पुनर्स्थापना का आवेदन उसी न्यायालय में पेश होगा जिस अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय निरस्त किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.12.2017 में यह भी दर्शाया है कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. को खारिज किया गया है, जो सही नहीं है। अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव ने अपने आवेदन में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपीलार्थी संख्या-2 बनने का अनुरोध किया था जो स्वीकार नहीं होकर अपीलार्थी को नायब तहसीलदार, सिरौही के आवेदन अनुसार अप्रार्थी के रूप में ही कायम रखा गया अर्थात् प्रकरण में अपीलार्थी पूर्व से पक्षकार था व अपीलार्थी को नयेसर पक्षकार बनने की आवश्यकता नहीं होने से अपीलार्थी को बतौर अप्रार्थी पक्षकार कायम रखा गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.12.2017 को निरस्त करते हुए राजस्व रेकॉर्ड में अपीलार्थी का नाम बतौर खातेदार पुनर्स्थापित किये जाने व उसके बाद प्रकरण की सुनवाई किये जाने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही को प्रदान किये जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/5 के विद्वान अधिवक्ता

....पेज चार पर

ने बहस में यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का आवेदन अर्न्तगत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता को विधि अनुरूप खारिज किया गया है। विवादित भूमि से अपीलार्थी का कोई लेना देना नहीं है एवं न ही अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि है। विवादित भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/8 के पिता/पति/दादा श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28.4.1975 के द्वारा बागाराम पुत्र पनजी, कौम नाई, निवासी- बारसा, तह. खारची, जिला- पाली के मुख्तारनामा आम उसके पुत्र गोपालराम से कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार, विवादित भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/8 के पिता/पति/दादा श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला के खातेदारी कब्जे-काशत की है, इसलिये अपीलार्थी की यह अपील खारिज की जावे। विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच विधि अनुरूप आदेश पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि नायब तहसीलदार, सिरोही ने पत्र क्रमांक/एन.टी./96/513 दिनांक 19.6.1996 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही को एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि कस्बा सिरोही में पुष्पमित्र सिंह देव पुत्र श्री जी. रामचन्द्र मीणा, निवासी- खारची, जिला- पाली कित्ता 9 रकबा 57 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार दर्ज चले आ रहे हैं, इन्होंने अपनी सम्पूर्ण आराजी का परित्याग कर दिया है, ये सिरोही में नहीं रहते हैं एवं न ही इस आराजी को काशत करते हैं, हर वर्ष बदलते हुये लोग इसे काशत करते हैं, इस आराजी का लगान भी इन्होंने कभी जमा नहीं कराया है, ये कहीं बाहर सरकारी कर्मचारी है, अतः राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 के नियम 61(1) के अर्न्तगत परित्याग करने की उद्घोषणा जारी कर नियमानुसार भूमि कब्जे सरकार लेने के आदेश जारी करावे। नायब तहसीलदार, सिरोही की उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में प्रकरण संख्या 1/96 पंजीयन किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम सिरोही प्रथम के खसरा संख्या 618/1/1, 622/1, 623, 624/1, 760, 761, 763, 764/1 व 770/1 रकबा क्रमशः 4.00 बीघा, 0.14 बीघा, 12.11 बीघा, 0.10 बीघा, 6.10-बीघा, 6.13 बीघा, 16.12 बीघा, 6.14 बीघा व 3.05 बीघा कुल कित्ता 9 रकबा 57 बीघा 09 बिस्वा भूमि के परित्याग की उद्घोषणा जारी की गई और उद्घोषणा की प्रति तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड, संबंधित भूमि के मौके पर एवं पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराई गई। साथ ही, उक्त उद्घोषणा का समाचार पत्र "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 28.6.1996 को प्रकाशन करवाया गया। प्रकरण में दिनांक 09.7.1996 को श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति- भील, निवासी- जैला ने जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में एक उजरदारी प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि पुष्पमित्र सिंह देव पुत्र श्री जी. रामचन्द्र मीणा, निवासी- खारची के खातेदारी की नहीं है, यह भूमि मेरे स्वयं की खरीदशुदा कब्जे काशत की खातेदारी भूमि है, जो मैंने पंजीकृत दस्तावेज ....पेज पांच पर

दिनांक 28.4.1975 के द्वारा बागाराम पुत्र पनजी, कौम-नाई, निवासी- बारसा, तहसील- खारची, जिला- पाली के आम मुख्तारनामा आम उसके पुत्र गोपालराम से खरिज कर कब्जा प्राप्त किया, तब से आज दिन तक काबिज काशत चला आ रहा हूँ, इसलिये परित्याग की घोषणा को खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही में उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान उक्त श्री बाबला पुत्र जोधाजी भील, निवासी- जैला ने जिला कलक्टर, सिरौही को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकरण को तहसीलदार, सिरौही के न्यायालय से अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:प.12(1)(2)कोर्ट/94/635-37 दिनांक 16.9.1996 के द्वारा -इस प्रकरण को सुनवाई हेतु तहसीलदार, सिरौही के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी, सिरौही के न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश दिये गये। जिस पर इस प्रकरण की पत्रावली तहसीलदार, सिरौही द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिरौही के न्यायालय को प्रेषित की गई। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:प. 12(1)(2)कोर्ट/94/668-71 दिनांक 27.9.1996 के द्वारा इस प्रकरण को सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, सिरौही के न्यायालय से तहसीलदार, रेवदर के न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश दिये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, सिरौही द्वारा इस प्रकरण की पत्रावली तहसीलदार, रेवदर को प्रेषित की गई। जिस पर तहसीलदार, रेवदर के न्यायालय में प्रकरण पंजीयन किया जाकर संबंधित को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:प.12(1)(2)कोर्ट/94/668-71 दिनांक 27.9.1996 के विरुद्ध उक्त श्री बाबला भील द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, सिरौही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने से राजस्व अपील अधिकारी, सिरौही द्वारा अपील संख्या 26/96 में पारित निर्णय दिनांक 15.5.97 के द्वारा उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, सिरौही के अधीनस्थ अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:12(1)(2)कोर्ट/94/830-33 दिनांक 05.6.1997 के द्वारा इस प्रकरण को सुनवाई हेतु तहसीलदार, रेवदर के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी, आवूपर्वत के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये। जिसके अनुसरण में इस प्रकरण की पत्रावली तहसीलदार, रेवदर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, आवूपर्वत के न्यायालय को प्रेषित की गई। जिस पर उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) आवूपर्वत के न्यायालय में प्रकरण पंजीयन हुआ। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:12(1)(2)कोर्ट/94/830-33 दिनांक 05.6.1997 के विरुद्ध उक्त श्री बाबला पुत्र जोधा जी, जाति- भील, निवासी- जैला द्वारा निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी/टि.ए./126/97/सिरौही दर्ज हुई। उक्त निगरानी याचिका में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा इस प्रकरण की पत्रावली तलब किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, आवूपर्वत द्वारा इस प्रकरण की पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी/टि.ए./126/97/सिरौही में पारित निर्णय दिनांक 18.5.1999 के द्वारा निगरानी खारिज की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

.....पेज छः पर

से इस प्रकरण की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत को भिजवाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत के न्यायालय में प्रकरण को सुनवाई हेतु पुनः नंबर पर लिया गया। सहायक कलक्टर, आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/96, 44/97, 51/99 अर्न्तगत धारा 61, 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरौही बनाम पुष्पमित्र सिंह देव व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.2.2000 के अनुसार विवादित कृषि-भूमि को कब्जे राज लेने के आदेश दिये गये व तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये।

प्रकरण में सहायक कलक्टर, सिरौही द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 12.2.2000 के विरुद्ध उक्त श्री बाबला द्वारा माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरौही, सिरौही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरौही द्वारा अपील संख्या: 57/2000 में पारित निर्णय दिनांक 18.6.2001 के द्वारा अपीलार्थी बाबला की अपील को खारिज (अस्वीकार) किया गया। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरौही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.6.2001 के विरुद्ध उक्त श्री बाबला पुत्र जोधाजी, जाति-भील, निवासी- जैला द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्ड पीठ द्वारा प्रकरण संख्या:अपील/डिक्री/134/01/सिरौही (4330/01) में पारित निर्णय 14.6.2010 के अनुसार अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरौही का निर्णय दिनांक 18.6.2001 एवं सहायक कलक्टर, आबूपर्वत का निर्णय दिनांक 12.12.2000 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार, सिरौही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर पक्षकारों को सुनवाई का एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नियमानुसार निर्णय पारित करें।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्ड पीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 14.6.2010 की पालना में तहसीलदार, सिरौही के न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या: 01/2010 पंजीयन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव की ओर से लिखित उजरदारी प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार, सिरौही के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.6.1996 को खारिज करने का अनुरोध किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही में अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव की ओर से धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भी एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के उक्त निर्णय दिनांक 12.12.2000 के द्वारा विवादित भूमि को कब्जा लेकर नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 30.12.2000 स्वीकृत कर दिया है एवं सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के उक्त निर्णय दिनांक 12.12.2000 के विरुद्ध अपील दर अपील होकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 14.6.2010 को निर्णय पारित कर सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के निर्णय दिनांक 12.12.2000 को निरस्त कर दिया है, इसलिये माननीय  
....पेज सात पर

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 14.6.2010 की पालना में राजस्व रेकॉर्ड में विवादित भूमि की बिलानाम से पूर्ववर्ती स्थिति बहाल की जाकर अपीलार्थी को वापस कब्जा दिलाया जाये।

प्रकरण में अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 04.12.2017 को खारिज किया गया है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही द्वारा इस प्रकरण में बाद सुनवाई अन्तिम निर्णय दिनांक 21.12.2017 को पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही द्वारा अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता को इस आधार पर खारिज किया गया है कि पुर्नस्थापना का प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में पेश होगा, जिस न्यायालय के निर्णय अथवा डिक्री को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के निर्णय दिनांक 12.12.2000 को निरस्त अवश्य किया गया है, परन्तु यह प्रकरण तहसीलदार, सिरौही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित भी किया गया है कि वे विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर पक्षकारों को सुनवाई का एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें। इससे, यह स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने निर्णय दिनांक 14.6.2010 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही को विवादित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कर प्रकरण में पक्षकारान की सुनवाई किये जाने के आदेश नहीं दिये हैं।

यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरौही द्वारा अपीलार्थी पुष्पमित्र सिंह देव के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता पर जो आदेश दिनांक 04.12.2017 पारित किया गया है, वह अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आता है तथा विधि अनुसार ऐसे अन्तरिम आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं होकर सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जानी चाहिये। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की यह अपील विधि अनुसार परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
सिरौही

